

Title:-"दादूपुर नलवी न्याय युद्ध" धरना 22,
अनाज मण्डी,शाहबाद,कुरुक्षेत्र(हरियाणा)

दादूपुर नलवी परियोजना को रद्द करना है गैरकानूनी और किसान-विरोधी-सुरजेवाला
'दादूपुर नलवी नहर परियोजना को रद्द करने के विरोध में कांग्रेस ने शाहबाद में किया धरना-विरोध प्रदर्शन'
कांग्रेस सरकार बनने पर बहाल करेंगे दादूपुर नलवी नहर परियोजना - सुरजेवाला
प्रेस विज्ञप्ति
शाहबाद, 22 अक्टूबर, 2017

दादूपुर नलवी परियोजना को प्रदेश मंत्रीमंडल द्वारा रद्द किया जाना किसान-विरोधी होने के साथ-साथ गैरकानूनी और संविधान के भी खिलाफ है। कांग्रेस इस जनविरोधी और गैरकानूनी कदम का हर स्तर पर विरोध करेगी। यह घोषणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज शाहबाद में पूर्व विधायक अनिल धंतौड़ी द्वारा आयोजित एक विशाल धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए की। दादूपुर नलवी नहर बचाने के लिए जारी न्याय-युद्ध के तहत क्रमिक भूख हड़ताल एवं धरना आज 51 वें दिन में प्रवेश कर गया।

धरना प्रदर्शन में किसान यूनियन के प्रधान व किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी और हरपाल सिंह के अलावा उत्तरी हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए हजारों किसानों ने भाग लेकर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा दादूपुर नलवी नहर परियोजना को रद्द करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। श्री सुरजेवाला के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के अनेक पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और नेताओं ने भी भाग लिया।

धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार का रवैया पूरी तरह से किसान-विरोधी है। किसानों को दादूपुर नलवी नहर परियोजना का पूरा मुआवजा देने की बजाए प्रदेश के मंत्रीमंडल ने इस संबंध में लाए गए एक संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ही गैरकानूनी रूप से इस परियोजना को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ है और इस संघर्ष में किसानों के हकों की लड़ाई को अदालत के अलावा विधानसभा के अंदर और बाहर भी मजबूती से लड़ा जायेगा।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश के किसान खट्टर सरकार के इस गलत फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस जनविरोधी फैसले से अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों के 225 गांवों की लगभग एक लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा, जिससे भाजपा की किसान विरोधी सोच का पता चलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इस फैसले से एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि उसे गरीबों और किसानों के हितों से कोई सरोकार नहीं है।

श्री सुरजेवाला ने याद दिलाया कि दादूपुर नलवी सिंचाई योजना 1985 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अक्टूबर 2005 में कांग्रेस ने ही एक बार फिर से इस योजना का नया चरण चालू किया और किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए शाहबाद फीडर, शाहबाद डिस्ट्रिब्यूटरी और नलवी डिस्ट्रिब्यूटरी के लिए 1019 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक लगभग 200 करोड़ रूपए भुगतान किए जा चुके हैं। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा इन नहरों को बनाने में 111 करोड़ 17 लाख रूपए खर्च किए जा चुके हैं। 300 करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च करने के बाद उत्तरी हरियाणा के लिए बेहद जरूरी इस परियोजना को रद्द करके खट्टर सरकार ने उत्तरी हरियाणा के लाखों किसान परिवारों के हितों पर कुठाराघात किया है।

‘सुरजेवाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं’ के नारों के बीच श्रीसुरजेवाला ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को फसलों के पूरे दाम दिए जाएंगे और उन्हें कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए कर्जा माफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारों ने किसान की फसल की ‘लागत +50 प्रतिशत मुनाफा’ देने का वायदा कर सत्ता हथियाई और सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले किसान-मजदूर के हकों पर कुठाराघात किया। किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज काहवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब करनाल-कुरुक्षेत्र-शाहबाद-अंबाला का किसान आलू व टमाटर की फसलें 2 रूपए किलो से भी कम की बिकावली के विरोध में सड़कों पर उतरा तो खट्टर सरकार ने उन पर लाठियाँ भांजी। यही हाल पापुलर व सफेदे की लकड़ी काहुआ, जिसके दाम 1200-1400 रूपए प्रति क्विंटल से गिरकर 600-800 रूपए प्रति क्विंटल तक आ गए और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ा।